

Fourteenth Loksabha**Session : 7****Date : 21-03-2006****Participants : Dangawas Shri Bhanwar Singh**

>

Title : Need to take steps for early release of funds to Non-Government Organisations engaged in providing meals to girls in hostels.

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राष्ट्र में महिला शिक्षा का अनुपात पुरूा शिक्षा के अनुपात में बहुत कम है। मैं यह भी मानता हूँ कि राज्य सरकारें व केन्द्र सरकारें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्राओं को भिन्न-भिन्न तरीकों से आर्थिक सहायता दे रही हैं। जैसे मुफ्त, पठन सामग्री, छात्रावासों की व्यवस्था ही नहीं परन्तु निःशुल्क भोजन व्यवस्था इत्यादि दिया जा रहा है। इनमें से कुछ राज्य सरकारें व कुछ भारत सरकार देती हैं।

महोदय जी, आपके माध्यम से मा० मानव संसाधन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारत में कई निजी शिक्षण संस्थायें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका/महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। यद्यपि मानव संसाधन मंत्रालय छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को छात्रावास में भोजन व्यवस्था में सहयोज देते हैं परन्तु इसमें बहुत विलम्ब होता है और कार्य पद्धति के कारण अधिकतर प्रतिवेदन स्वीकार ही नहीं होते हैं।

यदि ऐसी राशि राज्य सरकारों को आबंटन कर दी जाये तो संस्थाओं को स्वीकृत करने में आसानी होगी। यदि ऐसा नहीं करें तो शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के तीन माह में स्वीकृति कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। जुलाई माह में जबकि शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है, संस्थाओं से प्रतिवेदन आ जाने चाहिए व दो माह में मानव संसाधन मंत्रालय की राशि संस्थाओं को आबंटित हो जानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार मेरी प्रार्थना पर विचार करके मुझे निर्णय से सूचित करेंगे।